13 OCT 11 2026.qxd 12-10-2026 22:42 Page 1

चावल की कीमतों में 25 प्रतिशत तक उछाल

नयी दिल्ली। देश में चावल का उत्पादन घटने की आशंका के बीच इसकी कीमतों में 10-25त्न तक बढ़ोतरी हुई है। कम बारिश और अल नीनो की परिस्थितियों के चलते इस साल चावल के उत्पादन में करीब 4.5 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। इसका असर अगले साल चावल के निर्यात पर भी पड़ सकता है। भारत का चावल निर्यात 2027 में 4 प्रतिशत घटकर 2.4 करोड़ टन रह सकता है। देश में चावल की औसत खुदरा कीमत रविवार को 46.92 रुपये प्रति किलोग्राम रही। यह पिछले साल की तुलना में करीब 10त्न अधिक है। दक्षिण भारत में धान की बुवाई का रकबा घटने और बारिश की कमी के कारण सोना मसूरी, पोन्नी और स्वर्णा जैसी प्रीमियम गैर-बासमती किस्मों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 10-25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। चावल की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नजर है। जरूरत पड़ने पर सरकार बफर स्टॉक से चावल बाजार में उतार सकती है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, केंद्रीय पूल में सरकार के पास 3.8 करोड़ टन से अधिक चावल का भंडार है, जबकि 1 अक्टूबर के लिए बफर स्टॉक की निर्धारित जरूरत 1.025 करोड़ टन थी। इस अतिरिक्त भंडार का इस्तेमाल बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किया जा सकता है। इस साल देश में कम बारिश का असर अगले साल चावल के निर्यात पर पड़ सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग (स्ढ्ढ) के मुताबिक, भारत का चावल निर्यात 2027 में 4त्न घटकर 2.4 करोड़ टन रह सकता है। इसके पीछे टूटे चावल और सफेद चावल की विदेशी मांग में कमी, घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी और निर्यात के लिए उपलब्ध चावल की मात्रा घटने जैसे कारण हो सकते हैं।

अमेरिकी शुल्क घोषणा के बाद सौर कंपनियों के शेयर में 14 प्रतिशत से अधिक गिरावट

नयी दिल्ली। अमेरिका के कुछ भारतीय सौर उत्पादों पर 125.87 प्रतिशत का प्रारंभिक प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाए जाने की घोषणा के बाद सौर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर में बुधवार को भारी गिरावट दर्ज की गई।

बीएसई पर वारी एनर्जीज लिमिटेड का शेयर 14.99 प्रतिशत लुढ़क गया जबकि प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के शेयर में 14.23 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा, विक्रम सोलर लिमिटेड के शेयर में 7.47 प्रतिशत और स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में 1.41 प्रतिशत की गिरावट आई। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारतीय सौर उत्पादों को सरकार द्वारा अनुचित सब्सिडी दी जा रही है जिसके कारण 125.87 प्रतिशत का प्रारंभिक प्रतिकारी शुल्क घोषित किया गया है। अमेरिकी आदेश के अनुसार, 24 फरवरी 2026 को अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस) से क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या नहीं (सोलर सेल), के संबंध में प्रतिकारी शुल्क जांच में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा की। ये शुल्क अमेरिकी प्रशासन द्वारा 24 फरवरी से सभी देशों पर घोषित 10 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त हैं।

खुदरा महंगाई पहुंची 5.54 प्रतिशत पर

नयी दिल्ली। खाने-पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर यानी खुदरा महंगाई सितंबर में 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई अगस्त में 4.83 प्रतिशत रही थी। इस दौरान खुदरा खाद्य महंगाई अगस्त के 5.97 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 7.74 प्रतिशत दर्ज की गई। एक बार फिर शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में महंगाई की मार ज्यादा दिखी। शहरी इलाकों में मुद्रास्फीति की दर 4.88 प्रतिशत और ग्रामीण इलाकों में 6.08 प्रतिशत रही। ग्रामीण इलाकों में खुदरा खाद्य महंगाई 8.06 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 7.18 प्रतिशत रही। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में खाने-पीने की चीजों के अलावा रेस्त्रां एवं आवासीय सेवाएं एक साल पहले के मुकाबले 9.36 प्रतिशत और परिवहन सेवाएं 5.01 प्रतिशत महंगी हुई हैं। परिवहन सेवाओं में माल ढुलाई 15 प्रतिशत महंगी हुई और मुद्रास्फीति बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा। सोने-चांदी के दाम बढ़ने से निजी सौंदर्य प्रसाधन, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्ग में महंगाई दर 13.75 प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक ने गत 07 अक्टूबर को मौद्रिक नीति बयान में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई थी। उसने कहा था कि पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभावों का दूसरे चक्र का असर अब दिखने लगा है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त 2026) में खुदरा महंगाई 4.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। महंगाई के आज जारी आंकड़ों में बताया गया है कि सितंबर में प्याज की औसत कीमत एक साल पहले के मुकाबले 108 प्रतिशत, चांदी के गहनों की 88 प्रतिशत, अदरक की 63 प्रतिशत, लहसून की 55 प्रतिशत और नींबू की 36 प्रतिशत बढ़ी। वहीं, आलू 12 प्रतिशत, टमाटर नौ प्रतिशत, मोटर वाहन पांच प्रतिशत और भिंडी तथा नारियल चार-चार प्रतिशत सस्ता हुआ है।

संक्षिप्त

एशियाई खेलों में विजेता सैनिकोंसे रक्षामंत्री ने की मुलाकात

नयी दिल्ली (आससे.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियाई खेल 2026 में भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सोमवार को सैन्य खिलाड़ी दल से बातचीत के दौरान कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना के 92 खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। सीमित संख्या में भागीदारी के बावजूद यह विभिन्न सैन्य सेवाओं का एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पदक जीतना ही सफलता का पैमाना नहीं है। खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, मेडल हासिल न कर पाना, हार जाने का प्रतीक नहीं होता। हार तो तब होती है, जब हम कोशिश करना छोड़ दें। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए इसी लगन से तैयारी करने का संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने खिलाड़ियों को तैयार करने में मिशन ओलंपिक विंग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अब लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के लिए तैयारी मजबूत करने पर ध्यान देना होगा।

शिवराज पाटिल की जयंती पर ओम बिरला ने दी पुष्पांजलि

नयी दिल्ली (आससे.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज वी. पाटिल की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सांसदों, पूर्व सांसदों और संसद के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।12 अक्टूबर, 1935 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकुर गांव में जन्मे पाटिल ने 1991 से 1996 तक दसवीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में 17 विभाग-संबंधित स्थायी समितियों का गठन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत और संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण जैसी महत्वपूर्ण पहल हुईं। उनका निधन 12 दिसंबर, 2025 को हुआ था।

यहां भी पढ़ें
-:Website:-
www.ajhindidaily.com
-:For e-Paper:-
www.ajhindidaily.com/
आज गौरव शाली परंपरा का १०७वां वर्ष
निःशुल्क ई-पेपर सब्सक्राईब करें।

मौसम
सूर्योदय : ०५.५४
सूर्यास्त : ०५.३३
तापमान
अधि. : ३३.८
न्यून. : २२.८

देश में अराजकता का माहौल बना रही कांग्रेस-योगी



लखनऊ (आससे.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस व इंडिया गठबंधन न केवल आम जन को परेशान, बल्कि अव्यवस्था व अराजकता पैदा कर देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी कठघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पहचान का संकट खड़ा करने और भ्रष्ट मंसूबों के कारण कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपनी साख पूरी तरह खो चुके हैं और उनके इस गैर-राजनीतिक व्यवहार को देश की जनता भली-भांति देख रही है।` बातचीत में सीएम योगी ने कहा, आश्चर्य है कि चुनाव जीतने पर इनका पुरुषार्थ और हारने पर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोषी हो जाता है। न्यायालय अगर मेरिट के आधार पर कोई फैसला देता है, तो माननीय न्यायालय को भी कठघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। तमाम प्रकार की धमकियां देने का प्रयास होता है। ऐसे ही तमाम अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना, गाली-गलौच करना और अव्यवस्था फैलाना कांग्रेस की नियति का हिस्सा बन चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि जनता उन्हें हर बार क्यों ठुकरा रही है। 1985 के बाद से यूपी में कांग्रेस फिर नहीं आ पाई। यूपी की जनता ने कांग्रेस को 41 वर्ष पहले ही विदा कर दिया था। देश के अन्य राज्यों में भी लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है और वे इससे मुक्ति पा चुके हैं। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वे अपने अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी और जनता का विश्वास खो चुके नेतृत्व को बदलें। भारत में अराजकता न फैलाने और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास न करें। सीएम योगी ने कहा कि भारत की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बड़ी जागरूक है। वह इस अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जनता बहुत दिनों और बहुत देर तक यह सब बर्दाश्त करेगी। अगर कांग्रेस व उनके सहयोगी दलों ने अपने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कृत्य बंद नहीं किए तो उन्हें बचा-खुचा जनाधार भी गंवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने से बाज आए। जनता-जनार्दन और युवाओं को गुमराह करने से बाज आए। मेरिट के आधार पर और मुद्दों पर चर्चा कर के स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बने।

अस्पतालों में इलाज और सुविधाओं की दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य

नयी दिल्ली (आससे.)। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करने को कहा है। इसका उद्देश्य मरीजों को इलाज के खर्च की स्पष्ट जानकारी देना, बिलिंग संबंधी विवादों को रोकना और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है।केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दरें प्रदर्शित होने से मरीज और उनके परिजन इलाज पर होने वाले संभावित खर्च का अनुमान लगा सकेंगे और अपने चिकित्सा व्यय की बेहतर योजना बना सकेंगे। केंद्र ने चिकित्सा और आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों के लिए भी उपचार पैकेज की दरें पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

नोएडा के 12 और दिल्ली के दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

नोएडा/ नयी दिल्ली (आससे.)। नोएडा में सोमवार को करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वायड, डॉग स्क्वॉड और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सभी टीमें स्कूल परिसरों की जांच में जुट गईं। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। घटना के बाद स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस धमकी मिलने के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल जांच के बाद ही धमकी की वास्तविकता और उससे जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित दो स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी।

संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चला रही है भाजपा सरकार-अखिलेश

लखनऊ (आससे.)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और नौकरशाही भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चला रही है। सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही। देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। भाजपा देश के लिए संकट है। भाजपा सत्ता से हटेगी तभी संकट हटेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव अयोग का रवैया और कार्य भेदभावपूर्ण है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर को जीरो कर दिया है। अब दोबारा से वोट बनाने का अभियान चल रहा है, जिस एसआईआर प्रक्रिया में करोड़ो रुपए खर्च हुए, प्रचार हुआ। पूरा प्रशासन लगा अब उसे शून्य कर दिया गया। एसआईआर में किसी का फर्जी वोट नहीं बनना चाहिए था लेकिन मतदाता सूची में लाखों वोट फर्जी बन गए हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक आदमी के डबल वोट बने हैं, तीन-तीन, चार-चार, पांच और दस वोट तक बन गए हैं। आजमगढ़ की सदर विधानसभा में एक ही व्यक्ति के



दस वोट बन गए हैं। श्री यादव ने कहा कि चुनाव आयोग सामने आए और कहे कि वह भाजपा के इशारे पर काम नहीं करेगा। आयोग का अपनी विश्वसनीयता साबित करनी चाहिए। निष्पक्ष काम करना चाहिए। उन्होंने पीडीए जागरूक है। पीडीए कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता और सपा कार्यकर्ता भाजपा की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे।

डॉ.राम मनोहर लोहिया की पुण्य तिथि के अवसर पर गोमतीनगर स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से हर बूथ पर दो-दो सौ वोट बढ़ाने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव आयोग भाजपा और सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लखनऊ के सरोजनीनगर में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के वोट कटवाने के लिए दशरथ नाम के एक व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर से सौ फार्म भराए थे। वोट काटे जा रहे थे, समाजवादियों ने इसका खुलासा किया लेकिन चुनाव आयोग ने किसी पर कार्रवाई नहीं की।

किसी भी देश को दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए-उपराष्ट्रपति

नयी दिल्ली (आससे.)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान का आह्वान करते हुये कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश की सीमाओं



राष्ट्रीय संकल्प को राष्ट्रीय परिणामों में बदलना चाहिए

का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र समान है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। उपराष्ट्रपति ने आज यहां राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) के 66वें पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मूल्य राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला हैं और विश्व के साथ किसी देश के जुड़ाव का मार्गदर्शन करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हित संप्रभुता, लोकतंत्र,धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते परस्पर जुड़ाव का उल्लेख करते हुए राधाकृष्णन ने आतंकवाद,साइबर खतरों, महामारियों, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया।उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लक्ष्य विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनना है, लेकिन दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने या उन्हें अपनी शर्तें मनवाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी देश हम पर अनैतिक शर्तें न थोपे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता और आत्मसम्मान का सम्मान किया जाना चाहिए और देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए।

नेपाल में बचाव दल ने 95 लोगों को बचाया, पांच अभी भी लापता

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। गोरखा जिले में बाढ़ का पानी घरों और पुलों को बहा ले गया, जबकि पांच लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश में बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित इलाकों से 13 और लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके साथ ही अब तक कुल 95 लोगों को बचाया जा चुका है। नेपाली सेना, सुरक्षा बल और बचाव दल प्रभावित इलाकों में लोगों की तलाश करने के साथ-साथ राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। नेपाली सेना के मुताबिक, गोरखा जिले के चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है। रविवार शाम उंगिलुंग नदी के पास धौलीभीर इलाके में फंसे तीन लोगों को सेना के हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। यह इलाका चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका-6 में आता है। चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नारायण सापकोटा ने बताया कि रविवार सुबह अचानक हुए भूस्खलन के बाद तीनों लोग वहां फंस गए थे। उस जगह पर उनका मवेशियों को रखने का बाड़ा था। बाद में सेना के हेलिकॉप्टर से उन्हें सुरक्षित फिलिम पहुंचाया गया। रविवार शाम तक चार हेलिकॉप्टरों, जिनमें एक स्ब्ब-17 हेलिकॉप्टर भी शामिल था, और जमीन पर काम कर रही बचाव टीमों की मदद से 95 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राहत और बचाव कार्य में 700 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है। इनमें नेपाली सेना के 171 जवान भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग इलाकों से लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। बचाए गए लोगों में जगत से 17, यारू से 22, थुलोधुंगा से 13, दोभान से तीन, फिलिम से दो, न्याकफेदी से 17, पायु से 12, नामरुंग से तीन, डेंग से तीन और धौली से तीन लोग शामिल हैं। सेना और बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार तलाशी ले रहे हैं, ताकि लापता लोगों का पता लगाया जा सके। पहाड़ी क्षेत्र होने और भूस्खलन के खतरे के कारण राहत कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, इस आपदा में पांच लोग अब भी लापता हैं। इनमें दो महिलाएं शामिल हैं। बाढ़ और भूस्खलन ने इलाके के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। दो झूला पुल और दो मोटर वाहन पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा तीन जलविद्युत परियोजनाओं और मवेशियों को रखने के 34 बाड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। प्राधिकरण के अनुसार, 45 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 27 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। तीन वाहन भी बाढ़ के पानी में बह गए।

जेलेंस्की के लिए बढ़ी मुश्किलें

ओटावा/लंदन (एजेंसी)। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल प्रभाव से ऊर्जा सीजफायर लागू हो गया है। उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं। हालांकि, यूक्रेन को भी इस घोषणा की जानकारी अचानक मिली। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन सीजफायर का समर्थन करता है, लेकिन रूस को भी इसे स्वीकार करना होगा। रूस की ओर से सहमति की पुष्टि नहीं होने के कारण इस पहल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप से बातचीत के दौरान ऊर्जा सीजफायर का समर्थन किया। उन्होंने रूस से समझौते का पालन करने और ऊर्जा ढांचे तथा आम नागरिकों पर हमले तुरंत रोकने की अपील की। कार्नी ने यह भी कहा कि कनाडा अमेरिका को तेल और डीजल का निर्यात जारी रखेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा कि रूस ने सप्ताहांत में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। उनके मुताबिक, इन हमलों से आम नागरिक ठंड और अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस हमले रोकता है तो यूक्रेन सीजफायर के लिए तैयार है।

जेलेंस्की ने रविवार को आरोप लगाया कि रूस ने यूक्रेन के कई बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया। इनमें राजधानी कीव और खारकीव का एक-एक ऊर्जा संयंत्र शामिल है। इन हमलों से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के आसमान में पूरे दिन रूसी शाहेद ड्रोन उड़ते रहे। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण स्तर पर हमला शुरू करने के बाद से ऊर्जा ढांचे को लगातार निशाना बनाया है। इससे बिजली और हीटिंग की आपूर्ति में कमी आई है। यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाता रहा है। उसका कहना है कि इनसे रूस को युद्ध के लिए धन मिलता है।ऊर्जा सीजफायर के समर्थन के बीच रूस से डीजल खरीदने के अमेरिकी फैसले पर विवाद भी जारी है। ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा से दो दिन पहले रूसी डीजल पर अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देने वाले सौदे का एलान किया था। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने इसका विरोध किया। जेलेंस्की ने इसे कमजोर फैसला बताया। कार्नी ने भी कहा कि यह सौदा यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयासों के विपरीत है। सात अमेरिकी सीनेटरों, जिनमें चार रिपब्लिकन हैं, ने रविवार को इस सौदे को अवैध बताया। पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के बाधित होने से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी चिंता का विषय बनी हुई है।

ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलना चाहिए, जो युद्ध खत्म कर सके। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि देश का नेता कौन होगा, इसका फैसला यूक्रेन के लोग करेंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने जेलेंस्की और यूक्रेन सरकार को समर्थन जारी रखने की बात कही। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी यूक्रेन की स्वतंत्रता की लड़ाई में जेलेंस्की का समर्थन किया। कीव के कुछ नागरिकों ने भी ट्रंप की टिप्पणी पर चिंता जताई।

पूरा देश बनेगा जंतर-मंतर : दिपके

नयी दिल्ली (आससे.)। देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और धरना देने की जगह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, ऐतिहासिक जंतर-मंतर को अब निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसकी जगह रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थलों के तौर पर तय किया गया है। दिल्ली पुलिस के इस फैसले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और सह संयोजक सौरव दास ने सरकार पर निशाना साधा है। जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिपके ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर हटा दिया गया है। हां, अब यह विरोध-प्रदर्शन की जगह नहीं रही, क्योंकि वैसे भी उस कायर तानाशाह ने इसे युद्ध का मैदान बना दिया था।

पृष्ठ एक का शेष

गठबंधनके...

पर फोड़ने का आरोप लगाया। विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सोमवार का मार्च इसी विरोध का हिस्सा था।

ज्ञानेश कुमार...

बैरिकेडिंग करके लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। विपक्ष केवल यह सवाल पूछ रहा है कि चुनाव में धांधली नहीं हुई, इसका प्रमाण दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी सवाल के कारण राजधानी को ठप करने जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए राहुल ने उनसे सरकारी गवाह बनने और पद छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने गलती की है और इस्तीफा देना देश की सेवा होगी। राहुल ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया में लाखों लोगों के अधिकार छीने गए हैं और इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास इस मामले से जुड़ी जानकारी है और वह उचित मंच पर इसे उठाएगा।राहुल गांधी ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों, युवाओं और महिलाओं के खिलाफ दमन का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों में यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डरा हुआ है, जबकि विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बढ़ती सख्ती और अवरोध विपक्ष के आंदोलन को कमजोर करने के बजाय उसे और व्यापक बना रहे हैं। राहुल ने कहा कि विपक्ष पहले चुनाव आयोग जाने के दौरान रोका गया, फिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जाने से रोका गया और इसके बाद विपक्षी नेता राजघाट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखें तथा दबाव के आगे पीछे न हटें। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक संविधान की रक्षा, चुनाव व्यवस्था में सुधार और लोगों को न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। राहुल ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े लोग, यहां तक कि भाजपा के वे समर्थक भी, जो संविधान पर हमले को लेकर चिंतित हैं, इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इसे देश के भविष्य और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई बताया।

बदायूं...

थी। वैन की टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। हत्सा गांव में तीन दोस्तों की मौत की खबर पहुंचते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई और मातम छा गया। निखिल, रोहन और ऋषभ के परिवारों में गहरा शोक है। शिवा के अग्निवीर में चयन की खुशी अब गम में बदल गई है। मदनजुड़ी गांव के पास स्कूल वैन से बाइक की सीधी भिड़ंत हुई। चारों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे की जांच की जा रही है।

एफआईआर होगी...

हम कह रहे हैं कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से सीनियर वकील विकास सिंह और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। पिछले सोमवार को, राज्य सरकार ने वकील निखिल सराफ की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आरोपों में ट्रांसफर के लिए पैसे और मनमुताबिक नीतियां बनवाने के लिए पैसे का लेन-देन शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को सूचना भेजे जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया कि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए क्योंकि इनसे राज्य सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए जाएं। हाई कोर्ट के फैसले को कई आधारों पर चुनौती देते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि फैसले में कई कमियां हैं। सरकार का कहना है कि कोर्ट ने %प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट% (क्कस्क्र) की धारा 66(2) के तहत दी गई जानकारी को एक ऐसे निर्देश के तौर पर लिया जिससे केस दर्ज करना अनिवार्य हो जाता है, जो कि विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के खिल